समाचार संक्षेप

कोर्ट ने कहा - लगता है पब्लिसिटी के लिए लगाई याचिका

इंदौर,17 जून (ए)। शहर में वार्ड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन (क्राइसिस मैनेजमेंट) कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोट्र ने कहा ऐसा प्रतीत होता है केवल पब्लिसिटी के लिए यह याचिका लगाई है। याचिका कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, विनय बाकलीवाल एवं फौजिया शेख ने लगाई थी। इसमें इंदौर नगर निगम क्षेत्र में बनाई गई वार्ड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए कमेटियां निरस्त करने की मांग की थी। मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रफीक और विजय शुक्ला की युगल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा- इसमें कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो कमेटी कैसे गलत है। कोर्ट ने माना कि यह न्यायालय के हस्तक्षेप योग्य विषय नहीं है। याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने अपने तर्क रखे। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शेख अलीम ने तर्क रखे दोनों के तर्क सुनकर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

20 करोड़ के बिजली का बिल बचाने के लिए निगम ने सोलर पावर प्लांट के लिए कदम बढ़ाए

इंदौर,17 जून (ए)। निगम के जलूद के पास 500 करोड़ रुपये के सोलर पावर प्लांट की पदस्थापना के लिए ग्रीन मसाला बाण्ड जारी करने की तैयारी तेज शुरू कर दी है। प्लांट निर्माण के लिए 400 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसके लिए निगम ने विशेष टीम को लगाया है। अफसरों का दावा है कि जमीन सरकारी है, जिसे लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। जमीन मिलने के बाद लंदन और सिंगापुर स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से ग्रीन मसाला बाण्ड जारी करने की तैयारी शुरू होगी। पैसा जुटने के बाद प्लांट निर्माण के लिए एजेंसी को चुना जाएगा। सोलर प्लांट की स्थापना की जरूरत इसलिए पड़ी है, क्योंकि जलूद और यशवंत सागर आदि जगहों से जलप्रदाय के लिए निगम के वर्तमान में 20 करोड़ रुपये महीने का बिजली बिल चुकाना पड़ता है। जलूद के पास समराज गांव में बनने वाला प्लांट 100 मेगावाट क्षमता का होगा। अफसरों का कहना है कि उक्त प्लांट से निगम का बिजली बिल घटकर दस करोड़ रुपये रह जाएगा। इस माह प्लांट की लागत सात साल में वसूल हो जाएगी। सोलर पावर प्लांट की उम्र 25 साल मानी जाए, तो इस हिसाब से निगम को 18 साल तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। प्रदेश के किसी निकाय द्वारा सोलर ऊर्जा के लिए ग्रीन मसाला बाण्ड पहली बार जारी किए जा रहे हैं।

उज्जयिनी की सीमा में शिप्रा का श्रृंगार करो- आचार्य सत्यम

उज्जैन,17 जून (ए)। उज्जयिनी की सीमा में शिप्रा किनारे आदर्श पौधारोपण एवं उद्यानिकीरण उज्जयिनी के धार्मिक पर्यटन के लिए भी आवश्यक है। शिप्रा के उद्गम से चम्बल में संगम तक उसके दोनों किनारों पर उद्यानीकरण और शिप्रा के अस्तित्व की रक्षा के लिए उसके दोनों किनारों पर परिक्रमा पथ के निर्माण से न केवल धार्मिक पर्यटन बो बढ़ावा मिलेगा, अपितु लगभग 200 किमी की नदी की सीमा में हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। आज उज्जयिनी की सीमा में सम्राट अशोक और विक्रमादित्य के निवास भैरवगढ़ से पदयात्रा प्रारंभ हुई। सिद्धवट क्षेत्र तथा महावीर तपोभूमि के विकास के नाम पर सौदर्यीकरण एवं द्वारों का निर्माण हुआ, लेकिन शिप्रा के किनारे ही वृक्षविहीन है। भैरवगढ़ जेल का निर्माण उनसे पूर्व भगवान महावीर ने शिप्रा किनारे यहीं तपस्या की थी। पूर्वजों की मुक्ति का स्थल सिद्धवट तीर्थ सदियों से सनातन धर्मियों के लिए अत्याधिक धार्मिक महत्व का रहा है।

निजी अस्पतालों को उपलब्ध सुविधाओं की देनी होगी जानकारी

भोपाल,17 जून (ए)। कोरोना काल में निजी अस्पतालों में गड़बडिय़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पास शिकायतें पहुंची थीं। इनमें डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी के अलावा अन्य शिकायतें शामिल हैं। ऐसे में विभाग ने नियम और कड़े कर दिए हैं। अब निजी अस्पतालों को अपने यहां सुविधाओं और वार्डों के वास्तविक फोटोग्राफ सहित अन्य डिटेल सीएमएचओ को देने होंगे। निरीक्षण के दौरान इनमें गड़बड़ी मिलने पर अस्पताल के साथ सीएमएचओ पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि कोरोना काल में निजी अस्पतालों में ज्यादा बिलिंग और सुविधाओं की कमी की शिकायतें आई थीं। इसको देखते हुए अब पूरी जानकारी वास्तविक फोटो के साथ विभाग को भी देनी होगी।

भर्ती प्रक्रिया में अपेक्स बैंक ने दिया जवाब

भोपाल,17 जून (ए)। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) में 104 अधिकारियों की भर्ती से जुड़े मामले में बैंक प्रबंधन ने जांच अधिकारी को जवाब दे दिया है। वहीं, तत्कालीन प्रभारी प्रबंध संचालक प्रदीप नीखरा भी अपना पक्ष रख चुके हैं। अब उन अधिकारियों से भी उनका पक्ष लिया जा रहा है जो भर्ती संबंधी बैठकों में शामिल थे। इसके बाद जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। बैंक में 104 अधिकारियों की भर्ती में सेवा नियम का पालन नहीं करने की जांच सहकारिता विभाग करा रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी प्रबंध संचालक को पद से हटाकर आयुक्त कार्यालय में पदस्थ किया गया है। अभी भर्ती के लिए प्रांरभिक परीक्षा हुई है। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उसमें सेवा नियमों का पालन नहीं होने की बात सामने आई थी।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में महिला गाइड्स वन्यजीव प्रेमियों को दिखाएंगी बाघ

भोपाल,17 जून (ए)। कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व के बाद, अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में महिला टूरिस्ट गाइड्स वन्यजीव प्रेमियों को बाघ के दर्शन करवाएंगी। होशंगाबाद जिले में राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्यप्रदेश के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। इसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के लिए भारत की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। पार्क प्रबंधन ने स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी इस नेक पहल में सतपुड़ा में गाइड बनने के लिए 20 महिलाओं का चयन किया है। यह न केवल उन्हें सशक्त बनाने का, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की एक पहल है। स्थानीय महिलाओं को नौकरी के लिए चुनने का कारण यह है कि वे क्षेत्र के भूगोल, स्थलाकृति और वन्य जीवन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्रारंभ में, प्रबंधन, महिला गाइडों की भर्ती करने में झिझक रहा था, यह सोचकर कि मुश्किल से कुछ ही इसके लिए आगे आएंगे। उनकी धारणा में विपरीत, पास के पार्क क्षेत्रों की कम 50 से 60 महिलाओं में नौकरी के लिए आवेदन किया। इनमें से प्रबंधन ने 20 महिलाओं को चुना है जिन्हें अब नैचरलिस्ट (प्रकृतिवादियों) और वन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

भोपाल 17 जून (ए)। भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर आवाज, एनएसएस और यूनिसेफ ट्रस्ट द्वारा जिले में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें जरूरतमंद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया।

मंत्री बोर्ड की अलग से नहीं होगी सहायता योजना

भोपाल17 जून (ए)। प्रदेश में कोरोना से मृत अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वजन की सहायता के लिएएक ही योजना लागू होगी। मंडी बोर्ड भी इसके दायरे में आएगा। बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की थी। कृषि मंत्री और मंडी बोर्ड के अध्यक्ष कमल पटेल का कहना है कि अब प्रदेश में एक जैसी योजना लागू होगी। मंडी बोर्ड के 48 कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। बोर्ड के अध्यक्ष कमल पटेल ने मृतक के स्वजन को 25 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। बोड ने इसके आदेश भी जारी कर दिए थे लेकिन तब तक विशेष अनुग्रह योजना नहीं आई थी।

कलेक्टर बोले- भीड़ से नहीं बचे तो आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे

इंदौर,17 जून (ए)। जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार कम होता जा रहा है। मई में जहां एक दिन में 1800 के लगभग संक्रमित मरीज मिल रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा प्रतिदिन 50 मरीजों से भी कम की संख्या में सिमट गया है। इंदौर कुछ गतिविधियों को छोड़कर अनलॉक की स्थिति में है। शहरवासी प्रतिदिन अपने कामकाज के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। जेल रोड और राजवाड़ा के आसपास तंग बाजार में भीड़ के हालात चिंताजनक हैं। ऐसे में कलेक्टर मनीष सिंह ने शहरवासियों को कोरोना से बचने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं, जिन पर अमल कर शहरवासी कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। उन्होंने कहा शासन चाहे तो अभी सख्ती कर सकता है, लेकिन इससे परेशानी आम नागरिकों की होती है, इसलिए लोगों को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचना होगा। शहर के बाजार में भीड़ बढ़ रही है। इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने जैसे कोरोना प्रोटोकॉल की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाजार में क्रेता-विक्रेता कोरोना नियमों के पालन को औपचारिकता बनाए हुए हैं, जबकि अभी इन नियमों का पालन गंभीरता के साथ करने का समय है। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के बहुत कड़े और सख्त प्रयासों के बाद कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हो सका है। इसलिए कोरोना से बचाव के नियमों का पालन सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। कलेक्टर का कहना है कि वर्तमान में बाजार की हालत चिंताजनक बनी हुई है। शहरवासी चाहें तो इस स्थिति में भी अपने आपको कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। कलेक्टर सिंह ने कहा भीड़ में इन उपायों को अपनाकर स्वयं के साथ दूसरों को भी कोरोना से बचाएं।

शराब माफियाओं को क्यों तवज्जो देने में लगी है शिवराज सरकार?

भोपाल,17 जून (ए)। भारतीय जनता पार्टी के एक बुजुर्ग नेता के द्वारा कही गयी बात पर यदि भरोसा करें तो भाजपा भले ही इस प्रदेश में चौथी बार सत्ता पर काबिज हुई हो लेकिन उधार के सिंदूर से सुहागन बनी हुई है इस संबंध में उक्त नेता से विस्तार से पूछा गया तो उनका अजब-गजब तर्क था वह कहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग भले ही यह ढिंढोरा पीटें कि मध्यप्रदेश में 15 वर्षों तक सत्ता का वनवास भोगकर कमलनाथ के नेतृत्व में भले ही 15 महीने की क मलनाथ के नेतृत्व की जो कांग्रेस की सरकार चली वह अपने कर्मों और यदि शिवराज सिंह के आरोप पर भरोसा करें तो वल्लभ भवन की पांचवीं मंजिल को दलाली का अड्डा बनाने जैसे कई कारण तो हैं ही लेकिन मूल कारण कमलनाथ और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र मोह के चलते ज्योतिरादित्य सिधिया की उपेक्षा की यही नहीं यदि कुछ कांग्रेसियों की बात पर भरोसा करें तो 2018 के हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इन दोनों नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कम से कम 40 समर्थकों को अपनी रणनीति के चलते पराजय का स्वाद चखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ऐसे एक नहीं अनेकों कारण हैं जिनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से विदाई लेकर भाजपा का दामन थामने को मजबूर किया गया क्योंकि इस प्रदेश की राजनीति में यहां सिर्फ दो दलों का ही इस प्रदेश में प्रभाव रहता है तीसरा दल चाहे बसपा, सपा या आम आदमी पार्टी जिसने यहां के मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाने के लिये काफी मेहनत मशक्कत की और वह सफल नहीं हो पाई इसी दो दलीय राजनीति के चलते यहां कांग्रेस और भाजपा ही सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। हालांकि इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि इन्हीं सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी माँ से प्रदेश के शक्तिशाली और लोकप्रिय कहे जानेवाले कांग्रेस के डीपी मिश्रा से पंगा हुआ था और उसी के चलते इस प्रदेश में समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया की परिकल्पना के अनुरूप इस प्रदेश में सविद सरकार कुछ दिनों तक कायम हुई थी लगभग यही स्थिति कमलनाथ सरकार के काबिज होने के बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा की उस उपेक्षा के ही चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश किया और इस प्रदेश में पुनः चौथी बार शिवराज सिंह भले ही सत्ता पर काबिज हुए हों लेकिन उनकी इस सत्ता को भाजपा के अधिकांश नेता और राजनैतिक पंडित उधार के सिंदूर से सुगहन होना ही मानते हैं इस उधार के सिंदूर की बदौलत सत्ता पर काबिज हुए शिवराज सिंह ने उसी राह पर चलकर जिस राह पर चलकर वह प्रदेश में तीन बार सत्ता पर काबिज रहे यदि प्रदसिद्ध समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया के कहे जाने वाले शब्द सत्ताधारी नेताओं की दो जुबानें होती हैं, इस प्रदेश की सत्ता पर काबिज होते राजनेता उन्हीं डॉ. राममनोहर लोहिया के उन शब्दों को भी दोहराते यह कहते नजर आते हैं कि शिवराज की सत्ता की कार्यशैली की कथनी व करनी में काफी फर्क है वह जो कहते हैं वह करते नहीं हैं और जो करते हैं वह करते नहीं हैं, चौथी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद शिवराज ने एक नहीं अनेकों बार ऐसे शब्दों का उद्घोषन किया जिन्हें सुनकर आमजनता को यही लगता है कि कमलनाथ की सरकार तो भ्रष्ट थी लेकिन भाजपा की सरकार और उसके मुखिया शिवराज जैसा शासक शायद ही इस प्रदेश में हुआ हो, लेकिन वहीं भाजपा ही नहीं कांग्रेस के तमाम नेता शिवराज के शासनकाल का विवरण चटकारे लेकर करते नजर आते हैं ।

उसमें तो यही दिखता है कि शिवराज सिंह की कार्यशैली में कथनी और करनी में काफी अंतर है बाकी सबको छोड़ दिया जाये।

कोरोना के बाद नया कनेक्शन, नाम परिवर्तन, भार बढ़ाना होगा महंगा, कई सेवाओं के शुल्क और सर्विस चार्ज में 70 फीसदी तक वृद्धि की तैयारी

भोपाल,17 जून (ए)। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आपदा के बीच प्रदेश के बदहाल बिजली उपभोक्ताओं, दुकानदारों, उद्योग जगत को मप्र विद्युत नियाम आयोग ने एक जोरदार झटका दिया है। 12 वर्ष बाद आयोग द्वारा सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन लेने और वर्तमान भार में वृद्धि करने सहित विभिन्न सेवाएं के लिए लगने वाले शुल्क में 67 से 70 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की है। प्रदेश में लगभग 1.59 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें एक करोड़ घरेलू उपभोक्ता सस्ती (100 यूनिट पर 100 रुपए) बिजली योजना का लाभ पा रहे हैं। इसमें 28 लाख के लगभग कृषि उपभोक्ता हैं। शेष व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ता हैं। बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान चेक के मायम से भी करते हैं। अब चेक बाउंस हुआ तो घरेलू उपभोक्ताओं को 250 रुपए और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 1600 रुपए के लगभग देने होंगे। इसी तरह मीटर की जांच करानी हो या कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराना हो, भार बढ़ाने से लेकर सभी तरह के शुल्क और सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी की तैयारी है। मप्र ऊर्जा नियामक आयोग ने इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया है। शुल्कों में यह संशोधन 12 साल बाद होने जा रहा है। आयोग ने इसका ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। उभभोक्ताओं से सुझाव, दावे और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद सर्विस चार्ज में संशोधन लागू किए जाएंगे। उद्योगों के लिए बड़ा झटका - बिजली प्रदाय सुविधाओं के नाम पर प्रस्तावित बढ़ोतरी उद्योगं के लिए बड़ा झटका होगा। कोरोना के कारण पहले से छोटे उद्योग वर्किंग कैपिटल की समस्या से जूझ रहे हैं। आयोग ने आधा-अधूरा प्रकाशन कराया है। अंग्रेजी में प्रकाश कराना ही नियमों के विपरीत है। शुल्क बढ़ोतरी का कोई कारण नहीं बताया गया है। पिछले कोरोना काल में भी फिक्स चार्ज वसूला गया। इस बार भी कोई राहत नहीं दी गई। पहली आपत्ति तो ये कराएंगे कि इसका फिर से विधिवत प्रकाशन हिन्दी में कराया जाए। आयोग ने जो दरें प्रस्तावित की हैं, वह बहुत ज्यादा हैं। शुल्क धीरे-धीरे बढ़ाए जाने की जरूरत है। दावे-आपत्ति के लिए अंग्रेजी में आम सूची जारी की है। वह विद्युत अधिनियम की धारा 45(2)(ख) का उल्लंघन है। इसमें देरों की जानकारी और कारण तक नहीं दी गई है। आयोग ने प्रदेश के हिंदी अखबारों में अंग्रेजी में आम सूचना प्रकाशित कर उपाभोक्ताओं से पांच जुलाई 2021 तक आपत्ति/सुझाव मांगे हैं। इस पर जनसुनवाई की औपचारिकता छ- जुलाई को पूरी की जाएगी।

बीज की कमी के चलते किसान हो रहे परेशान, उत्पादन घटने के आसार

इंदौर,17 जून (ए)। भारत के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक मध्यप्रदेश में खरीफ सत्र की बुआई की तैयारियों में जुटे हजारों किसान इस तिलहन फसल के अच्छे बीजों की कमी से परेशान हैं। जानकारों के मुताबिक इस संकट के समय रहते दूर न होने पर राज्य में पीले सोने के रूप में मशहूर इस नकदी फसल की पैदावार में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बीच, राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोयाबीन की खेती को घाटे का सौदा करार देते हुए किसानों को सलाह दी है कृषक संगठन किसान सेना के सचिव जगदीश रावलिया ने प्रदेश में सोयाबीन के मानक बीजों की बड़ी किल्लत है। निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा मौके का फायदा उठाते हुए सोयाबीन का बीज नौ हजार रुपये से 12 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बेचा जा रहा है ।

भोपाल 17 जून (ए)। इन्दौर में कोरोना महामारी के समय आम जनता ही नहीं स्वयं सरकार आक्सीजन से जूझ रही मगर इसके बाद भी आज यह आलम है कि इन्दौर में पेड़ों की खुलेआम कटाई का दौर जारी है.

भोपाल 17 जून (ए)। मंत्री विश्वास सारंग ने चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की।

महिला एवं बाल विकास विभाग में डेढ़ करोड़ रुपये की हेराफेरी

भोपाल,17 जून (ए)। महिला एवं बाल विकास विभाग में डेढ़ करोड़ से अधिक रुपये के गबन का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद दो लेखापाल समेत 94 खाताधारक कर्मचारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। इन अधिकारी-कर्मचारियों के खाते में सांठगांठ कर दोगुना वेतन व भत्ते जमा किए गए। रुपयों के बारे में आरोपितों ने विभाग से इसकी जानकारी छिपा ली और राशि को अपने निजी उपयोग में खर्च किया। इस संबंध में तत्कालीन आयुक्त ने जांच की और बाद में क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने जांच में पाया कि वर्ष 2015 से 2016 के बीच की यह हेराफेरी की गई है। इस मामले में जांच जारी है। एएसपी क्राइम ब्रांच गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि धोखाधड़ी और सरकारी पैसों का गबन के संबंध में महिला बाल विकास की ओर से लेखा इंचार्ज शहजाद खान ने करीब तीन माह पूर्व शिकायत की थी। शिकायत की जांच में पाया गया कि विभाग के सभी तरह से कर्मचारियों के खाते में इस दौरान दोगुनी वेतन डाली गई। इन कर्मचारियों में परियोजना अधिकारी भी शामिल हैं। इस वेतन या पैसों के संबंध में किसी कर्मचारी ने न तो विभाग को बताया और न ही यह राशि लौटाई। विभाग की ओर से जब जांच और ऑडिट कराया गया तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को लेखाल काशी प्रसाद, सिराज खान समेत 94 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। एएसपी क्राइम ब्रांच गोपाल धाकड़ का कहना है कि कोषालय के अधिकारियों की भूमिका भी सदेह के घेरे में है।